



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 2017/कार्तिक 15, 1939

No. 427]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2017/KARTIKA 15, 1939

## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(कार्मिक संबंध प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय)

### अधिसूचना

मुम्बई, 25 सितम्बर, 2017

**फा. सं. सी.ओ.: ई.आर.डी.: 4489: 2017.**—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5), की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्र सरकार की पिछले मंजूरी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **(अधिकारी)** सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है: अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **(अधिकारी)** सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकता है ।  
(2) इन विनियमों में अन्यथा वर्णित प्रावधानों को छोड़कर इन्हें 1 नवंबर, 2007 के दिन से प्रभावी, समझा जाएगा ।
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **(अधिकारी)** सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद जिन्हें उक्त विनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के विनियम 3 में,-  
(i) खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -  
'(एफ) "परिवार" का अर्थ है अधिकारी का पति या पत्नी, पूरी तरह से निर्भर अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चे और कानूनी तौर पर अपनाये गये बच्चों सहित), चालीस प्रतिशत या अधिक निःशक्तता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन और सामान्यतः साथ रहने वाले और अधिकारी पर पूरी तरह से निर्भर माता पिता ।  
**स्पष्टीकरण.**— इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई बच्चा या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन, अधिकारी पर तभी निर्भर माना जाएगा यदि ऐसे बच्चे, माता पिता, भाई या बहन की मासिक आय रु. 3500 प्रति माह से अधिक नहीं है ।  
परंतु यह और कि यदि माता-पिता में से एक की आय रु. 3,500 प्रति माह से अधिक हो या माता-पिता दोनों की कुल आय रु. 3,500 प्रति माह से अधिक हो, तो माता-पिता दोनों को पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर नहीं माना जाएगा ।  
(ii) खंड (ओ) को छोड़ा जाएगा ।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, -

(I) उप-विनियम (4ए) का छोड़ दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4ए) के रूप में तो छोड़े जाने के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को सन्निविष्ट किया जाएगा अर्थात्: -

"(5) 1 नवंबर, 2007 से, प्रत्येक ग्रेड के सापेक्ष निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होना:

**(क) उच्च कार्यपालक ग्रेड**

वेतनमान VII = रु. 46800-1300/4-52000

वेतनमान VI = रु. 42000-1200/4-46800

**(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड**

वेतनमान V = रु. 36200-1000/2-38200-1100/2-40400

वेतनमान IV = रु. 30600-900/4-34200-1000/2-36200

**(सी) मध्यम प्रबंधन ग्रेड**

वेतनमान III = रु. 25700-800/5-29700-900/2-31500

वेतनमान II = रु. 19400-700/1-20100-800/10-28100

**(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड**

वेतनमान I = रु. 14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700

स्पष्टीकरण.- प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2007 को लागू वेतनमानों से विनियमित होता है, 1 नवंबर, 2007 के इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में स्तर से स्तर के आधार पर फिट किया जाएगा, अर्थात् तत्संबंधित स्तरों पर पहले चरण से संबंधित चरणों पर और वेतन वृद्धि सामान्य रूप से आबिदकी तारीख, अन्यथा निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, पर आएगी।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए सर्वदा इन सभी ग्रेड में अधिकारियों का सेवारत होना आवश्यक है."

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में, -

(ए) उप विनियम (1), निम्नलिखित उप-विनियम के लिए, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अधीन, पर और 1 नवंबर, 2007 को एवं से वेतनवृद्धियां निम्नलिखित अधीन दी जाएंगी, अर्थात्:-

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में निर्धारित वेतनमानों में निर्दिष्ट संबंधित वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और जिस माह में देय है, उस माह के पहले दिन प्रदान की जाएगी;

(बी) ऐसे अधिकारी, जो कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल में उच्चतर स्केल के अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के उपरांत मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II में चले गए हैं, प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण होने पर चार गतिरोध वेतन वृद्धियों के पात्र होंगे, जिनमें से प्रथम दो रु. 800 प्रत्येक और अगली दो रु. 900 प्रत्येक की होंगी;

परंतु जिन अधिकारियों ने दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद 1 नवंबर, 2007 को तीन वर्ष या अधिक पूरे कर लिये हैं, को 1 नवंबर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि और दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होने के छह साल की समाप्ति पर 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद एक अन्य गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होगी;

(सी) मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II के अधिकारी जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के उपरांत मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल III के वेतनमान में चले गए हैं, वे प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए रु. 900 प्रत्येक की तीन गतिरोध वृद्धियों के लिए पात्र होंगे।

परंतु जिन अधिकारियों ने प्रथम गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद 1 नवंबर, 2007 को तीन वर्ष या अधिक पूरे कर लिये हैं, को 1 नवंबर, 2007 से अगली गतिरोध वेतनवृद्धि और प्रथम गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होने के छह साल की समाप्ति पर 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद उत्तरवर्ती गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होगी:

परंतु यह और कि मूल मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल III में नियुक्त या पदोन्नत अधिकारी प्रत्येक तीन वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए रु.900 प्रत्येक की 4 गतिरोध वेतनवृद्धियों के पात्र होंगे या:

परंतु यह और भी कि ऐसे अधिकारी जो पहले से ही दो गतिरोध वेतनवृद्धियां प्राप्त कर चुके हैं तथा दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद 1 नवंबर, 2007 को तीन साल से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें 1 नवंबर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होगी दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होने के बाद छह वर्ष पूर्ण होने पर 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त होगी:

स्पष्टीकरण, इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में इस तरह की वेतनवृद्धि पदोन्नति नहीं होगी और अधिकारियों के अधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेंगे।

(बी) उप-विनियम (2) में,-

(i) स्पष्टीकरण में खंड (ई) के बाद एवं नोट से पहले, निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा अर्थात्: -

"(एफ) नवंबर, 2007 के पहले दिन से, अन्य बातों के समान होने के बावजूद, व्यावसायिक वेतन की मात्रा निम्नानुसार संशोधित हो जाएगी: -

तालिका

जो लोग इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की जूनियर एसोसिएट या इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टीफाइड एसोसिएट पास कर चुके हैं	i. रु.410 प्रति माह, अधिकतम स्केल तक पहुंचने के एक वर्ष बाद
जो लोग इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टीफाइड एसोसिएट के दोनों पार्ट पास कर चुके हैं	i. रु. 410 प्रति माह, अधिकतम स्केल तक पहुंचने के एक वर्ष बाद
	ii. रु. 1030 प्रति माह अधिकतम स्केल तक पहुंचने के दो वर्ष बाद

बशर्ते कि, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जूनियर एसोसिएट या इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का सर्टीफाइड एसोसिएट (एक या दोनों भाग) की योग्यता रखने वाले अधिकारी को सर्टीफाइड एसोसिएट प्राप्त करने की तारीख से, व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त जारी की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन के बाद की किस्त, पहली किस्त जारी होने की तारीख के आधार पर जारी होगी:

बशर्ते ऐसे मामले में जहां एक अधिकारी ने, ऊपर की कोई योग्यता पहले से ही हासिल कर ली है और इस तरह के योग्यता के लिए व्यावसायिक योग्यता वेतन के लिए कोई वेतन वृद्धि नहीं मिली है, तो उसे व्यावसायिक योग्यता वेतन दिनांक 01 नवंबर 2007 या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख, जो बाद में हो, से उस तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन दिया जाएगा।

(ii) खंड (v) के लिए, नोट में, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा: -

"(V) यदि किसी अधिकारी ने 27 अप्रैल 2010 से पहले से ही खंड (iv) में निर्दिष्ट कोई योग्यता हासिल कर ली है और ऐसी योग्यता के लिए उसे कोई भी वेतन वृद्धि या व्यावसायिक योग्यता वेतन नहीं मिला है, तो उसे दिनांक 01 नवंबर, 2007 या ऐसी योग्यता अर्जन की तिथि, जो भी बाद में हो, "उस तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन दिया जाएगा। "

(सी) उप-विनियम (3) में, -

(I) खंड (डी) के बाद और नोट से पहले, निम्न खंड, को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(ई) 1 नवंबर 2007 को और उसके बाद से अन्य मदें समान होने के कारण, मकान किराया भत्ता के साथ व्यक्तिगत स्थायी वेतन निम्न दरों पर दिया जाएगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए यही रहेगा: -

**तालिका**

वेतन वृद्धि की राशि (रु.)	01.11.2007 को वेतन वृद्धि राशि पर महंगाई भत्ता (रु.)	देय कुल स्थायी व्यक्तिगत वेतन, जहां बैंक द्वारा आवास की सुविधा प्रदान की जाती है (रु.)
(ए)	(बी)	(सी)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394

(ii) नोट में, खंड (i) और (ii) के लिए निम्न खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे: -

"(i) खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) की तालिका (सी) के अंतर्गत दर्शाये गए स्थायी व्यक्तिगत भत्ता या स्थायी व्यक्तिगत वेतन का भुगतान उन अधिकारियों को किया जाएगा, जिन्हें बैंक द्वारा आवास प्रदान की जाती है।

(ii) जब नियामक 4 के उप-विनियम (2), (3), (4) या (5) में विनिर्दिष्ट वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि दी जा रही हो, तो अधिकारियों को स्थायी व्यक्तिगत भत्ता या स्थायी व्यक्तिगत वेतन के लिए मकान किराया भत्ता के लिए पात्र राशि खंड (ई) के तहत दी गई सारिणी में कॉलम (ए) और (बी) में निर्दिष्ट कुल राशि और संबंधित अधिकारी को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता होगा।

(iii) नोट में नंबरों को पुनः बदलकर उप-खंड (v) करने के बाद, निम्नलिखित खण्ड को जोड़ा जाएगा: -

"(V) उपर्युक्त खंड (ए) के अनुसार, जिस अधिकारी को अग्रिम वेतन वृद्धि मिली है, उसे वेतनमान में अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद, खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) में उल्लेख के अनुसार स्थायी व्यक्तिगत भत्ता/स्थायी व्यक्तिगत वेतन मिलेगा।

5. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 21 में, -

(i) उप-विनियम में (3), नोट को हटा दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4), नोट को हटा दिया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम और नोट को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

"(5) 01 नवंबर, 2007 के 1 दिन और उसके बाद से, अखिल भारतीय औसत कामगार श्रेणी उपभोक्ता मूल्य सूची (सामान्य) आधार 2836 अंकों से प्रत्येक 4 अंकों की बढ़ोतरी-कमी के लिए  $19.60 = 100$  आधार पर वेतन का 0.15% महंगाई भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण, - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, -

(ए) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" से आशय मूल वेतन है और इसमें

गतिरोध वेतन वृद्धि शामिल है;

(बी) विनियम 5 के उप-विनियम 2 के स्पष्टीकरणों (सी), (डी), (ई) तथा (एफ) के अनुसार, महंगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन को लिया जाएगा।

6. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) और (2) के लिए निम्न उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से,

(ए) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है, उसके वेतनमान के पहले चरण में मूल वेतन का 1.75 प्रतिशत के बराबर या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(बी) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवास की सुविधा प्रदान नहीं की गई है, उसे निम्न तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जाएगा:

#### तालिका

कार्य स्थल	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(I) मेजर 'ए' क्लास शहर और समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

यदि किसी अधिकारी द्वारा किराये की रसीद प्रस्तुत की जाती है तो उन्हें देय मकान किराया भत्ता, उनके वेतनमान में पहले चरण के 1.75 प्रतिशत से अधिक भुगतान किया जाने वाला वास्तविक किराया होगा, बशर्ते अधिकतम राशि उपर्युक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार उस स्थान पर देय मकान किराया भत्ता का 150% होगी।

(2) 01 नवंबर, 2007 को उसके बाद से -

(ए) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है, उसके वेतनमान के पहले चरण में मूल वेतन का 1.20 प्रतिशत के बराबर या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(बी) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवास की सुविधा प्रदान नहीं की गई है, उसे निम्न तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जाएगा:

#### तालिका

कार्य स्थल	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(I) मेजर 'ए' क्लास शहर और समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

बशर्ते कि यदि किसी अधिकारी द्वारा किराये की रसीद प्रस्तुत की जाती है तो उन्हें देय मकान किराया भत्ता, उनके वेतनमान में पहले चरण के 1.20 प्रतिशत से अधिक भुगतान किया जाने वाला वास्तविक किराया होगा, बशर्ते अधिकतम राशि उपर्युक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार उस स्थान पर देय मकान किराया भत्ता का 150% होगी।

नोट-जो अधिकारी अपने मकान में रहकर, मकान की लागत से सम्बद्ध भत्ते का दावा करते हैं, उनके लिए भी उस स्थान पर देय मकान किराया भत्ता का अधिकतम 150% तक सीमित होगा।

7. उपर्युक्त नियमों के नियम 23 के अनुसार: -

(I) उप-नियम (1) में, "1 नवंबर 2002 का" के आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "1 नवंबर 2007" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) उप-नियम में (2), “1 नवंबर 2002” के आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “1 नवंबर 2007” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) उप-नियमों (3) के लिए, (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3) 1 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से यदि एक अधिकारी उस क्षेत्र में सेवारत है, जिसे ग्रुप ए या ग्रुप बी के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में निर्दिष्ट किया जाना है, तो वह ग्रुप ए या ग्रुप बी के क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार रु 290 प्रतिमाह या रु 255 प्रतिमाह के दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते का पात्र होगा।

(4) 1 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षिक वर्ष के बीच में एक से दूसरे स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा उसके एक या अधिक बच्चों, पूर्व स्थान में, स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह स्थानांतरित स्थान में रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी बच्चों के लिए रु.700 प्रतिमाह के दर से शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते का पात्र होगा, परंतु सभी बच्चों के पूर्व स्थान पर पढ़ाई समाप्त होने के साथ ही यह भत्ता समाप्त हो जाएगा।

(5) 1 मई, 2010 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर की सेवा में प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियों को प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिसके लिए उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, 7.75 प्रतिशत की दर से अधिकतम 2300 रुपये प्रति माह तक प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वह ले सकता था, यदि वह बैंक की सेवा में तैनात होता, ले पाएगा:

बशर्ते यदि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां उसे प्रतिनियुक्ति से तुरंत पहले तैनात किया गया था, तो उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर अधिकतम रु.1200 प्रति माह तक प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा।

परंतु यह और कि संकाय सदस्य के रूप में बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.1200 प्रति महीने के प्रतिनियुक्ति भत्ते हेतु पात्र होगा. ”;

(iv) उप-विनियम (8) के लिए, निम्न उप-नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(8) 1 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, यदि एक दिन के कार्य अवधि को दो घंटे के न्यूनतम अंतराल के साथ विभाजित किया जाता है, तो अधिकारी स्प्लिट ड्यूटी भत्ते हेतु रु 165 प्रति माह की दर से पात्र होगा. ”;

(v) उप विनियम (10) में, -

(ए) “1 नवंबर 2002 का” के आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “1 नवंबर 2007” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(बी) तालिका के लिए, निम्न तालिका, प्रतिस्थापित की जाएगी :-

**तालिका**

स्थान (1)	दर (2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक लेकिन कम से कम 1500 मीटर की ऊंचाई वाला स्थान और मर्कुरा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम रु.550 प्रति माह के अध्यक्षीन
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन कम से कम 3000 मीटर की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2 <sup>1/2</sup> % अधिकतम रु.680 प्रति माह के अध्यक्षीन
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु.1570 प्रति माह के अध्यक्षीन

8. खंड (ए) के लिए उप-विनियम (1) में दिए गए नियमों के नियम 24 में, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

“(ए) चिकित्सा व्यय: 1 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, अधिकारी अपने व परिवार हेतु चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए, उसके द्वारा किए गए व्ययों के विवरण के साथ अपने प्रमाणपत्र के आधार पर किए गए दावों के लिए निम्न तालिका के अनुसार पात्र होगा:-

**तालिका**

ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
जूनियर प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन ग्रेड	रु. 5100 या खर्च की गयी राशि जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यकारी ग्रेड	रु. 6320 या खर्च की गयी राशि जो भी कम हो

ध्यान दें- (i) एक अधिकारी को अनुपभुक्त चिकित्सा सहायता जमा करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि उपर्युक्त अधिकतम राशि तीन गुने से अधिक कभी न हो;

(ii) वर्ष 2007 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को नवंबर 2007 और दिसंबर, 2007, दो महीने के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा,

स्पष्टीकरण :- इस विनियम के प्रयोजन हेतु, -

(i) एक अधिकारी के मामले में 100 प्रतिशत तथा उसके परिवार के मामले में 75 प्रतिशत तक अस्पतालीकरण हेतु आवश्यक सभी मामलों में अस्पतालीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी या;

(ii) 1 मई 2010 को और उसके बाद से, इस विनियम के तहत अस्पतालीकरण के खर्चों की प्रतिपूर्ति 27 अप्रैल, 2010 के कामगार कर्मचारियों के लिए द्विपक्षीय समझौते के तहत निर्धारित अस्पतालीकरण योजना के नियम और शर्तों के अनुसार निम्नलिखित तालिका में निर्धारित सीमा के अधःधीन की जाएगी।

**तालिका**

(ए) जूनियर प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I और मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II और III	(i) बेड चार्ज स्वयं- रु.700 प्रति दिन परिवार- रु.525 प्रति दिन (ii) अन्य शुल्क वर्कमेन कर्मचारियों हेतु अस्पतालीकरण योजना के तहत 125% के सीमा पर निर्धारित
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV और V तथा उच्च कार्यपालक ग्रेड वेतनमान VI और VII	(i) बेड चार्ज स्वयं- रु.900 प्रति दिन परिवार- रु.675 प्रति दिन (ii) अन्य शुल्क कामगार कर्मचारियों हेतु अस्पतालीकरण योजना के तहत 150% के सीमा पर निर्धारित";

9. उप-विनियम (2) के लिए उपर्युक्त नियमों के नियम 25 में, निम्न उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात: -

"(2) उप-विनियम (1) में निहित नियमों के बावजूद, 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा उसके वेतनमान के प्रथम स्तर के मूल वेतन का 1.20 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, भुगतान किए जाने पर बैंक द्वारा उसे आवास की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते कि जहां अधिकारी को निवास के साथ फर्नीचर भी प्रदान किया गया है, अधिकारी द्वारा वेतन के प्रथम स्तर के मूल वेतन का, जिसमें उसे रखा गया है, 0.25 प्रतिशत के बराबर और राशि बैंक द्वारा वसूली जाएगी।

परंतु यह और कि जहां ऐसे आवास बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं, बिजली, पानी, गैस और संरक्षण के लिए शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

10. उपर्युक्त विनियम के 36 वें विनियम में, उप- विनियम (2) के बाद, निम्न उप- विनियम को रखा जाएगा. जो निम्नानुसार है:-

"(3) 01 मई, 2010 से, गर्भाशय मामलों के लिए अधिकतम 45 दिनों की छुट्टी, 12 महीनों की समग्र अवधि की सीमा के अंदर स्वीकार की जा सकती है।"

11. उपर्युक्त विनियम के 41वें नियामक, उप-विनियम (4) के, खंड (ए) में निम्नलिखित खंडों को जोड़ा जाएगा:-

'(ए) विराम भत्ता- 01 मई 2010 और उसके बाद से अधिकारी, जिनका स्केल/ ग्रेड कॉलम (1) में दर्शाया गया है, उनका प्रत्येक दिन का विराम भत्ता की राशि कॉलम (2) के अनुसार होगी :-

#### तालिका

अधिकारियों का ग्रेड/ स्केल	प्रमुख 'ए' क्लास के शहर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	रु.	रु.	रु.
वेतनमान IV या उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए	1000	800	700
स्केल I/II/III के अधिकारियों के लिए	800	700	600

परंतु यह कि वेतनमान IV व उससे ऊपर के अधिकारी चार महानगर आउटस्टेशनों यथा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में कार्य पर जाते हैं, तो उन्हें दिया जाने वाला विराम भत्ता रु.1200/- प्रति दिन होगा, तथा स्केल I/II/III अधिकारियों के लिए रु.1000/- प्रति दिन होगा,

परंतु यह और कि इस बात का भी प्रावधान है कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम है, लेकिन चार घंटे से अधिक है, उपरोक्त दरों से आधे का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण, - विराम भत्ता की गणना के लिए, हवाई यात्रा की दशा में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के समय से आगमन तक की कुल अवधि चौबीस घंटे या उसके किसी भाग को "प्रत्येक दिन" माना जाएगा, जहां अनुपस्थिति की अवधि चौबीस घंटों से कम होने की दशा में, न्यूनतम आठ घंटों की अवधि को प्रति दिन माना जाएगा।

12. उपर्युक्त विनियम के 42वें विनियम में, सब-विनियम (3) के बाद, निम्न सब- विनियमों को रखा जाएगा:-

"(4) 04 मई 2010 को और उसके बाद से, स्थानांतरण पर अधिकारियों को, पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामानों को बीमा करने, आदि से जुड़े खर्चों के लिए निम्न तालिका के अनुसार एकमुश्त रकम दी जाती है:-

#### तालिका

ग्रेड	लगभग
शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	रु.12,000
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु.9,000

13. उपर्युक्त विनियम के 44वें विनियम में, उप-विनियम (3) में, निम्न प्रावधानों को शामिल किया जाएगा:-

" परंतु यह कि 01 मई माह 2010 से कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I का अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए सबसे कम किराया वाले इकॉनोमी श्रेणी में हवाई यात्रा करने के लिए पात्र है. ऐसी दशा में, वास्तविक किराया या उतनी दूरी के लिए ऐसी प्रथम श्रेणी के रेल किराया में जो भी कम है, उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी. यह नियम मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II और III के अधिकारियों द्वारा अवकाश रियायत का लाभ लेते समय भी लागू होगा, जहां दूरी 1000 किलो मीटर से कम है."

14. उपर्युक्त विनियम के 45वें विनियम में,,-

(i) उप-विनियम (1) में, निम्न प्रावधानों को शामिल किया जाएगा अर्थात:-

" परंतु यह कि 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में आए अधिकारियों के लिए कोई भविष्य निधि नहीं होगी";



(ii) उप-विनियम (3) में, खंड (बी) के बाद और नोट से पहले निम्न शामिल किया जाएगा :-

“(सी) अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत कवर अधिकारी, जिन्होंने पेंशन योजना को नहीं चुना है, वे अंशदायी भविष्य निधि योजना में ही रहेंगे”.

(iii) उप-विनियम (3) के बाद, निम्न उप-विनियम को शामिल किया जाएगा अर्थात :-

“(4) दिनांक 01 अप्रैल, 2010 के बाद बैंक में भर्ती अधिकारी, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कवर होंगे, जिसमें अधिकारी द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत का अंशदान किया जाएगा और भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ़ नं.5/7/2003-ईसीबी & पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003 और इसमें समय-समय पर हुए संशोधनों से अधिसूचित नई पेंशन योजना के लिए बैंक द्वारा उतनी ही राशि का अंशदान दिया जाता है।

15.

### “यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 की अनुसूची

#### (विनियम का उप-विनियम (2) देखें)

एक अधिकारी, 1 नवंबर, 2007 से प्रभावी नीचे दी गयी तालिका के अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ता पाने का तब तक पात्र होगा, जब तक कि इसे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वापस न ले लिया जाए या संशोधित न कर दिया जाए :

#### तालिका

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.14,700/- से कम मूल वेतन पाने वाले	रु.14,700 / - से अधिक मूल वेतन पाने वाले
1	2	3	4
1.	<b>मिजोरम</b>		
	(ए) मिजोरम का चिंपतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलेई जिले में ही लुंगलेई शहर से 25 किमी. से दूर के क्षेत्र।	2000	2600
	(ख) मिजोरम के लुंगलेई शहर से 25 किमी. दूर के क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला।	1600	2100
	(सी) मिजोरम का पूरा आइजोल जिला	1200	1500
2.	<b>नागालैंड</b>	1600	2100
3.	<b>अंडमान व नीकोबार द्वीप समूह</b>		
	(ए) उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, नीकोबार और नारकोंडम द्वीप	2000	2600
	(ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	1600	2100

4.	<b>सिक्किम</b>	2000	2600
5.	<b>लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह</b>	2000	2600
6.	<b>असम</b>	320	400
7.	<b>मेघालय</b>	320	400
8.	<b>त्रिपुरा</b> (ए) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र (ख) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे त्रिपुरा राज्य में	1600 1200	2100 1500
9.	<b>मणिपुर</b>	1200	1500
10.	<b>अरुणाचल प्रदेश</b> (ए) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र (ख) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे अरुणाचल प्रदेश में	2000 1600	2600 2100
11.	<b>जम्मू और कश्मीर</b>  ए) कठुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोडी ख) उधमपुर जिला: (i) भाग 2(बी) में शामिल क्षेत्रों के अलावा डूडू बसंतगढ़, लैंडर भामाग इलाका, (ii) कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और मोहरे तहसील में कियासी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र	2000  2000 1600	2600  2600 2100
	सी) डोडा जिला: पैडर का इलाका और किशतवाड़ तहसील में नियाबत नौगांव  डी) लेह जिला: जिले का संपूर्ण क्षेत्र  ई) बारामूला जिला (i) पूरा गुरेज - निराबात, तंगदार उप-मंडल और केरन इलाका (ii) मन्चिल	2000  2000 2000 1600	2600  2600 2600 2100

	<p>एफ) पृच्छ और राजौरी जिला:</p> <p>पृच्छ और राजौरी जिले के क्षेत्र, जिनमें पृच्छ और राजौरी शहर और सुंदरबनी और इन दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्र शामिल नहीं हैं.</p> <p>जी) उपर्युक्त (ए) से (एफ) में शामिल न किए गए क्षेत्र, परंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किमी. के दायरे में आने वाले क्षेत्र या ऐसे स्थान, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने स्टाफ सदस्यों के लिए समय-समय पर बार्डर भत्ता हेतु पात्र घोषित किया जाता है.</p>	1200	1500
	<p>जी) उपर्युक्त (ए) से (एफ) में शामिल न किए गए क्षेत्र, परंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किमी. के दायरे में आने वाले क्षेत्र या ऐसे स्थान, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने स्टाफ सदस्यों के लिए समय-समय पर बार्डर भत्ता हेतु पात्र घोषित किया जाता है.</p>	1200	1500
12.	<p>हिमाचल प्रदेश</p> <p>(ए) चंबा जिला</p> <p>(i) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायत: बदगाँव, बाजोल, देओल कुगती, नयागाम और टुंडा, गांव: जगत ग्राम पंचायत का घाटू, चौहाटा ग्राम पंचायत का कनरसी</p> <p>(ii) भरमौर तहसील</p> <p>उपर्युक्त मद (i) में शामिल किए गए पंचायतों और गांवों को छोड़कर</p> <p>(iii) भटीयट तहसील में झंडरू पंचायत, चुरा तहसील डलहौजी टाउन (बानीखेत मुख्य सहित) .</p>	2000	2600
	<p>(ii) भरमौर तहसील</p> <p>उपर्युक्त मद (i) में शामिल किए गए पंचायतों और गांवों को छोड़कर</p>	1600	2100
	<p>(iii) भटीयट तहसील में झंडरू पंचायत, चुरा तहसील डलहौजी टाउन (बानीखेत मुख्य सहित) .</p>	1200	1500
	<p>(बी) किन्नौर जिला:</p> <p>(i) असरंग, चितकुल और हंगो कुनो / चारंग पंचायत, छोटा खंबा की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर 15/20 क्षेत्र, नाथपा और रूपी, पूह उप-मंडल, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर.</p> <p>(ii) उपर्युक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला.</p>	2000	2600
	<p>(ii) उपर्युक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला.</p>	1600	2100
	<p>(सी) कुल्लू जिला:</p> <p>(i) खरगा, कुशवर और सारगा की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित</p>		

कर निरमंड तहसील के 15/20 क्षेत्र	2000	2600
(ii) बाहरी-सरज (निरमंड तहसील में जकत-खाना और बरो के गांवों को छोड़कर) तथा बाहरी सेराज क्षेत्र और पंडराबिस के परगना को छोड़कर लेकिन जकत-खाना और निरमंड तहसील के बरो गांवों सहित पूरा जिला).		
(डी) लाहौल एवं स्पीति जिला:	1200	1500
लाहौल एवं स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र		
(ई) शिमला जिला:	2000	2600
(i) कूट, लबाना-सदन, सरपारा और चाडी-ब्रांदा की पंचायतों को सम्मिलित कर रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र		
	2000	2600
(ii) डोरा- कवार तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत कशापठ तहसील तथा सराहन परगना के मुनीश, घोरी चायबीस.	1600	2100
(iii) सराहन परगना के चौपाल तहसील तथा घोरीस, पंजगाँव, पटसनऊ, नौबीस और तीनकोटि, तकलेश क्षेत्र, परगना का देवथीग्रामपंचायत, बरबिस परगना, रामपुर तहसील के रामपुर परगना का कस्बा रामपुर और घोरीनोग, शिमला टाउन और उपनगर उसके (ढल्ली, जतोग, कसूम्टी, मशोबरा, तारादेवी और तुतु).	1200	1500
(एफ) कांगड़ा जिला:		
(i) बारा भंगल और छोटा भंगल के क्षेत्र	1600	2100
(ii) कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर और नगर निगम सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय है, लेकिन धर्मशाला टाउन महिला आईटीआई, दारी, यांत्रिक कार्यशाला, रामनगर, बाल कल्याण और शहर और देश योजना कार्यालयों, सकोह, लोवर सकोह में स्थित सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, दुगीयार,, एचआरटीसी कार्यशाला, सधेर, जोनल मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, दारी, आईपीएच - उप-मंडल, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर. कंगरा जिले का पालमपुर शहर जिसमें पालमपुर का एचपीकेवीवी कैम्पस और पालमपुर नगर निगम सीमा के बाहर स्थित निम्न कार्यालय शामिल होंगे:		
एच पी कृषि विश्व विद्यालय कैम्पस, मवेशी विकास कार्यालय / जर्सी फार्म, बानूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय / भारत-जर्मन		

	कृषि कार्यशाला / एचपीपीडब्ल्यूडी प्रभाग, बुंदला विद्युत उप-मंडल, लोहना, डीपीओ निगम बुंदला, विद्युत एचईएसईई प्रभाग, घुग्गर.	1200	1500
	(जी) मंडी जिला: जोगिन्द्रनगर तहसील की छोहर घाटी, बागरा की थूंग तहसील में पंचायत, चत्री, छोटीधर, गरागुशाइन, गाढू, गर्यास, जंजेहली, जरयार, जोहर, कलहानी, कलवा, खोलनाल, लोथ, सिलिबागी, सोमचान, थचदार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक-बिंगा के पंचायत, कमला, सकलाना, तन्यर और तरखोला, कारसोग तहसील-बलीधर के तहसील, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहुदी, माँज, पेखी, साइंज, सराहन और टेवन, सुंदरनगर तहसील-बोही के पंचायत, बटवारा, धन्यारा, पौराकोठी, सेरी और शोजा. (एच) सिरमौर जिला: बानी के पंचायत, (पछड़ तहसील), भरोग भेनेरी, पांवटा तहसील), बिरला (नाहन तहसील), डिब्बर (पछड़ तहसील) और थाना कासोगा (नाहन तहसील) और ठांसगिरी ट्रेक. (i) सोलन जिला: मंगल पंचायत (जे) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त मद क्र. (ए) से (आई) शामिल नहीं है.	1200	1500
		1200	1500
		320	400
13.	<b>उत्तराखंड</b> चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग तथा चंपावत जिलों के अंतर्गत क्षेत्र	2000	2600"

**स्पष्टीकरण ज्ञापन**

विनियम जिन्हें पूर्व प्रभाव से लागू किया गया है, संबंधित बैंकों द्वारा इस संबंध में दिये गये विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ तथा बैंकों के उच्चस्तरीय अधिकारी संघों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त ज्ञापनों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार हैं. इस प्रकार ऐसे पूर्व प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

फाइल संख्या-----

आर.आर.मोहंती, महाप्रबंधक(मासं)

[विज्ञान -III / 4/ असा./297/ 17 ]

नोट: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक.....को प्रकाशित किये गये थे तथा उसके उपरान्त निम्नांकित अधिसूचनाओं के जरिये संशोधित किये गये:-

क्र.सं.	अधिसूचना क्र.	दिनांक
1.	ओएसआर/1	14.11.1987
2.	ओएसआर/2	04.06.1988
3.	ओएसआर/3	04.06.1988
4.	ओएसआर/4	30.12.1989
5.	ओएसआर /5	27.10.1990
6.	ओएसआर/6	11.01.1992
7.	ओएसआर/7	12.12.1992
8.	ओएसआर/8	27.02.1993
9.	ओएसआर/9	25.09.1993
10.	ओएसआर/10	10.09.1994
11.	ओएसआर/11	07.01.1995
12.	ओएसआर/12	07.09.1996
13.	ओएसआर/13	21.12.1996
14.	ओएसआर/14	21.12.1996
15.	ओएसआर/15	21.12.1996
16.	ओएसआर/15	06.02.1996
17.	ओएसआर/16	03.06.2000
18.	ओएसआर/16	30.12.2000
19.	ओएसआर/17	09.12.2000
20.	ओएसआर/18	29.10.2002
21.	ओएसआर/19	18.06.2003
22.	ओएसआर/20	27.01.2006
23.	ओएसआर/21	10.03.2007

**UNION BANK OF INDIA**  
**(EMPLOYEE RELATIONS DIVISION, CENTRAL OFFICE)**  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 25th September, 2017

**F. No. Co : ERD : 4489 : 2017.**—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(5 of 1970), the Board of Directors of the Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Union Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1)These regulations may be called the Union Bank of India (Officers') Service(Amendment) Regulations,2017.

(2)They shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.

2. *In the Union Bank of India* (Officers') Service Regulations, 1979(hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-

- (i) for clause (f), the following clause shall be substituted ,namely:-

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children(including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.’

- (ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

- (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;

- (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) With effect from the 1<sup>st</sup> November,2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

**(a) Top Executive Grade**

Scale VII = Rs.46800-1300/4-52000

Scale VI-Rs.42000-1200/4-46800

**(b) Senior Management Grade**

Scale V = Rs.36200-1000/2-38200-1100/2-40400

Scale IV = Rs.30600-900/4-34200-1000/2-36200

**(c) Middle Management Grade**

Scale III = Rs.25700-800/5-29700-900/2-31500

Scale II = Rs.19400-700/1-20100-800/10-28100

**(d) Junior Management Grade**

Scale I = Rs.14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700.

Explanation.- Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31<sup>st</sup> October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1<sup>st</sup> November, 2007 on stage to stage basis, i. e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(6) Nothing in sub-regulation (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”.

4. In regulation 5 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely:-

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation(5) of regulation 4, on and from the 1<sup>st</sup> November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely:-

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of which first two shall be Rs. 800 each and next two Rs. 900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1<sup>st</sup> November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1<sup>st</sup> November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1<sup>st</sup> November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

- (c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1<sup>st</sup> November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1<sup>st</sup> November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1<sup>st</sup> November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or:

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1<sup>st</sup> November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1<sup>st</sup> November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1<sup>st</sup> November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation,-Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

(b) in sub-regulation(2),-

(i) in the Explanation, after clause(e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Pay shall stand revised as under:-



TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	i. Rs. 410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	i. Rs. 410 per month after one year on reaching maximum of the scale. ii. Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers(either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment of Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1<sup>st</sup> November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

(ii) in the Note, for clause(v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) if an officer, as on the 27<sup>th</sup> April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause(iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later,”;

(c) in sub-regulation(3),-

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) on and from the 1<sup>st</sup> November, 2007 other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided(Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”,

(ii) in the Note, for clause(i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b),(c),(d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank’s accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2), (3),(4) or (5) of regulation 4 is earned.”;

(iii) clause(e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause(v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

“(v) An officer who has earned the advance increment as in clause(a) above shall draw the quantum of fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay mentioned in clauses (b),(c),(d), or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation(3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation(4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

“(5) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of pay.

Explanation,- For the purposes of this sub-regulation,-

(a) ”pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d),(e) and (f) to sub-regulation(2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per

cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007,-

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:-

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.-The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2002”, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2002, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3),(4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
  - (3) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs. 290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
  - (4) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
  - (5) On and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of

7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organization which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs. 1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.”;

- (iv) for sub-regulation(8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) on and from the 1<sup>st</sup> day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.”;

- (v) in sub-regulation(10),-

- (a) for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2002”, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November, 2007” shall be substituted;
- (b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2 <sup>1/2</sup> % of pay subject to a maximum of Rs.680 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month”;

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

- “(a) Medical Expenses:- On and from the 1<sup>st</sup> day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 6320 or the amount incurred whichever is less

**Note-** (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

**Explanation.-** for the purposes of this regulation,-

- (i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation or;
- (ii) On and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27<sup>th</sup> day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

**TABLE**

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self- Rs.700 per day</p> <p>Family- Rs.525 per day</p> <p>(ii) Other charges</p> <p>At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self- Rs.900 per day</p> <p>Family-Rs.675 per day</p> <p>(ii) Other charges</p> <p>At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;</p>

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub- regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation(2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(3) With effect from the 1<sup>st</sup> day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation(4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) Halting Allowance- On and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/ Scales of officers	Major ‘A’ Class Cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs. 1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

**Explanation,-** For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

“TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12,000
Middle Management and Junior Management	Rs.9,000”.

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation(3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that with effect from the 1<sup>st</sup> May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.

14. In regulation 45 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation(1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1<sup>st</sup> day of April, 2010,”;

- (iv) In sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;

- (v) After sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1<sup>st</sup> day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributed Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F. No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22<sup>nd</sup> December, 2003, as amended from time to time.”

15.

**“Schedule to Union Bank of India (Officers’) Service Re regulations, 1979**

**(See sub-regulation (2) of regulation 23)**

With effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
1.	<b>Mizoram</b>		
	(a) Chimpui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. From Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. From Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram.	1200	1500
2.	<b>Nagaland</b>	1600	2100
3.	<b>Andaman and Nicobar Islands</b>		

	<p>(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands.</p> <p>(b) South Andaman (including Port Blair).</p>	<p>2000</p> <p>1600</p>	<p>2600</p> <p>2100</p>
4.	<b>Sikkim</b>	2000	2600
5.	<b>Lakshadweep Islands</b>	2000	2600
6.	<b>Assam</b>	320	400
7.	<b>Meghalaya</b>	320	400
8.	<b>Tripura</b>		
	(a) Difficult areas of Tripura.	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	<b>Manipur</b>	1200	1500
10.	<b>Arunachal Pradesh</b>		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh.	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	<b>Jammu and Kashmir</b>		
	a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	b) Udhampur District:		
	(i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100



	<p>c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil</p> <p>d) Leh District: All places in the District</p> <p>e) Barmulla District: (i) Entire Gurez- Nirabat , Tangdar Sub-Division and KeranIllaqua.  (ii) Matchill.</p> <p>f) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.</p> <p>g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. From the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.</p>	<p>2000</p> <p>2000</p> <p>2000</p> <p>1600</p> <p>1200</p> <p>1200</p>	<p>2600</p> <p>2600</p> <p>2600</p> <p>2100</p> <p>1500</p> <p>1500</p>
12.	<p><b>Himachal Pradesh</b></p> <p>(a) Chamba District.</p> <p>(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil ,Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata.</p> <p>(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.</p>	<p>2000</p> <p>1600</p>	<p>2600</p> <p>2100</p>

	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rup, Pooh Sub-Division ,excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(c) Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj(excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District:	2000	2600
	Entire area of Lahaul and Spiti		
	(e) Shimla District:		

	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi- Branda.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghor Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon , Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District:		
	(i) Areas of Bara Bhawal and Chhota Bhawal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town- Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H- Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project,		

	<p>Shamnagar.</p> <p>Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town—H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.</p>	1200	1500
	<p>(g) Mandi District:</p> <p>Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil- of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gattoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block-Binga, Kamla, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil-Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil- Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura Kothi, Seri and Shoja.</p> <p>(h) Sirmaur District:</p> <p>Panchayats of Bani, Bakhali, (Pachhad Tehsil), Bharg Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract</p> <p>(i) Solan District:</p> <p>Mangal Panchayat</p> <p>(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.</p>	<p>1200</p> <p>1200</p> <p>1200</p> <p>320</p>	<p>1500</p> <p>1500</p> <p>1500</p> <p>400</p>

13.	<b>Uttarakhand</b> Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600''

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

File Number-----

R.R.MOHANTY, General Manager(Hr)

[ADVT.-III/4/Exty./297/17]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India on----- and subsequently amended vide following notifications, namely:-

Sr. No.	Notification No.	Date
1.	OSR/1	14.11.1987
2.	OSR/2	04.06.1988
3.	OSR/3	04.06.1988
4.	OSR/4	30.12.1989
5.	OSR/5	27.10.1990
6.	OSR/6	11.01.1992
7.	OSR/7	12.12.1992
8.	OSR/8	27.02.1993
9.	OSR/9	25.09.1993
10.	OSR/10	10.09.1994
11.	OSR/11	07.01.1995
12.	OSR/12	07.09.1996
13.	OSR/13	21.12.1996
14.	OSR/14	21.12.1996
15.	OSR/15	21.12.1996
16.	OSR/15	06.02.1996
17.	OSR/16	03.06.2000
18.	OSR/16	30.12.2000
19.	OSR/17	09.12.2000

20.	OSR/18	29.10.2002
21.	OSR/19	18.06.2003
22.	OSR/20	27.01.2006
23.	OSR/21	10.03.2007